

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर (राज०)

पीठारीन अधिकारी :- हरि राम मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या:-68/2022

(223 आई.टी.एफ.)

जी.सी.एम.एस. संख्या:-2022/116

उनवान

1. लैण्ड होल्डर तहसीलदार मण्डरायल जिला करौली राजस्थान।

...वादी / अधीनार्थ।

बनाम

1. जमना पुत्र रतनलाल जाति ब्राह्मण
2. विद्या देवी उर्फ लक्ष्मी देवी बेवा परसादी जाटव जाति
3. हल्के पुत्र सामलिया जाति जाटव

सभी निवासीयान रोधई तहसील मण्डरायल करौली राजस्थान।

.....प्रतिवादीनम / रसमंडे।

उपरिथत:-

1. श्री रामजीलाल अग्रवाल अधिवक्ता अपीलार्थ।
2. श्री लियाकत अली अधिवक्ता रसमंडेन्ट सं० 02।
3. श्री रामसहाय पाराशर अधिवक्ता रसमंडेन्ट सं० 03।
4. पैरोकार सरकार उपस्थित।

--: निर्णय :-

दिनांक: 08.07.23

1. यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड मण्डरायल जिला करौली, दायर मुकदमा संख्या 10/2021 अन्तर्गत धारा 17C राजस्थान कास्टवारा अधिनियम 1955, बउनवान लैण्ड होल्डर बनाम जमना लाल दगैरह में पारित निर्णय दिनांक 14.09.2022 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 22C राजस्थान कास्टकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद अन्दर प्रस्तुत की गई है।
2. प्रकरण में सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद पत्र अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी मण्डरायल के समक्ष इस आशय का पेश कि खसत नंबर 1480 वाके ग्राम रोधई में परसादी पुत्र कुडेरी जाटव के नाम खातेदारी में दर्ज है। परसादी जाटव जाति से जाटव होने के कारण उक्त आराजीयात अनुसूचित जाति की आराजीयात की है। परसादी जाटव के फौत होने के बाद से उक्त आराजीयात पर अनुसूचित जाति

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

काबिज है। प्रतिवादी सं० 01 जाति से ब्राह्मण है जो सवर्ण जाति में आता है। परसामी जाटव ने उक्त आराजीयात को अपनी मृत्यु से पूर्व प्रतिवादी सं० 01 को गलत तरीके से हस्तांतरित की है। अतः प्रतिवादी को उक्त आराजीयात से वेदखल कर आराजी को सिवायचक घोषित की जावे। प्रतिवादी सं० 2/1 ने ऑर्डर 7-रूल-11 प्रार्थना पत्र पेश किया। मातहत अदालत ने दिनांक 14.09.2022 को निर्णय पारित करते हुए प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र ऑर्डर 7-रूल-11 स्वीकार फरमा कर वादी का वाद पत्र वाद कारण के अभाव में खारिज कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है।

3. अपील मीमों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्त/वादी ने इस मातहत अदालत के समक्ष पेश वाद पत्र में फर्जी कुटरचित एवं अनरजिस्टर्ड दस्तावेज का अपने दावा का आधार नहीं बनाया गया है बल्कि विधि अनुसार जब कोई सवर्ण जाति का व्यक्ति अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के व्यक्ति की खातेदारी की भूमि पर किसी भी कारण से कब्जा कर लेता है और उस भूमि के अवैध हस्तान्तरण में स्वयं भूमि के खातेदार अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के व्यक्ति की भूमिका संदिग्ध ही जाती है तो ऐसा हस्तान्तरण विधि अनुसार धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अवैध होता है। इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए मातहत अदालत ने प्रार्थना पत्र रैस्पोंडेंट आदेश 7-नियम-11 विधि विरुद्ध तरीके से स्वीकार कर दावा अपीलान्त खारिज कर दिया गया।

आदेश 7-नियम-11 जा० दी० के प्रार्थना पत्र को तय करने का विधि का यह सुव्यवस्थित सिद्धान्त है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में दर्ज तथ्य के आधार पर ही आदेश 7-नियम-11 के प्रार्थना पत्र का निरस्तारण किया जा सकता है ना कि विपक्षी द्वारा की गयी जवाब देही के तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र को तय किया जावे। अपीलान्त द्वारा अपने दावा की ताईद में जमना लाल रैस्पोंडेंट को जमीन विक्रीद को विक्रय करने का दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत किया है। इस पर योग्य मातहत अदालत ने मनन न करके प्रार्थना पत्र आदेश 7-नियम-11 मंजूर करने में योग्य मातहत अदालत ने कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार कर मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी का निर्णय 14.09.22 को अपारत फरमाया जावे।

4. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करी हुए उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।
5. मुख्य बहस में अधिवक्ता अपीलान्त ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अदालत मातहत ने जमनालाल रैस्पोंडेंट को विक्रय किये दस्तावेज के बावत आदेश 7-नियम-11 के प्रार्थना पत्र पर यह तय करना कि वह रजिस्टर्ड है या

अनरजिस्टर्ड है कोई अधिकार प्राप्त नहीं है क्योंकि जब अपीलांट द्वारा अपने वाद पत्र में यह स्पष्ट दर्ज किया है कि परसादी पुत्र कुड़ेरी ने जमीन विवादित को रेस्पोंडेंट जमनालाल को विक्रय कर दी गयी तो इन तथ्यों पर योग्य अदालत मातहत को दावे में दोनों पक्षों की पूर्ण शहादत लेकर ही वाद पत्र को तय करना चाहिये था।

आगे कथन किया कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 11.04.2002 को प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से पूरी तरह स्पष्ट था कि खसरा नंबर 1480 पर प्रतिवादी नंबर 01 जमनालाल काबिज है जो सवर्ण जाति का है। जो गैरकानूनी है पटवारी हल्का रोधई की इसी रिपोर्ट को आधार बना कर तत्कालीन भूमि के खातेदार परसादी व भूमि पर काबिज सवर्ण जाति के जमनालाल शर्मा को वहसियत प्रतिवादी दर्ज कर दावा विधि अनुसार मातहत अदालत के समक्ष पेश किया था लेकिन इन महत्वपूर्ण तथ्यों पर गौर किए बिना ही मातहत अदालत ने अपीलांट/वादी का वाद पत्र खारिज कर दिया। अतः न्यायालय हाजा से निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी मण्डरायल का निर्णय दिनांक 14.09.2022 को निरस्त किया जावे।

6. जवाब बहस में रेस्पोंडेंट संख्या 01 द्वारा पैसेकार सरकार की बहस को ही दोहराया गया। प्रकरण को रिमाण्ड करने बाबत निवेदन किया।
7. जवाब बहस में रेस्पोंडेंट संख्या 03 के अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलांट व रेस्पोंडेंट संख्या 01 मिलकर रेस्पोंडेंट संख्या 03 से मिलित कर उसके खातेदारी को हड़प कर ली गई, जबकि रेस्पोंडेंट संख्या 02 का इस आराजीयात से कोई संबंध सरोकार नहीं है। उनके द्वारा वाद में प्रस्तुत जवाब दावा के विशेष कथन के जिम्मेदार नंबर 01 की और ध्यान दिलवाया जाकर कथन किया कि परसादी का वारिसान रेस्पोंडेंट संख्या 03 हैं। रेस्पोंडेंट संख्या 02 का ताईद तक कोई वारता नहीं है। अपीलांट/वादी द्वारा बिलकुल गलत व मनगडंत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है तथा वादी अप्रार्थी ने एक फर्जी व कुटरचित तथा अनरजिस्टर्ड दस्तावेज को आधार बना कर मन माने तौर पर रेस्पोंडेंट्स को परेशान करने की गरज से दावा हाजा पेश किया गया था। रेस्पोंडेंट सं० 02 द्वारा एवं उसके मृतक पति द्वारा कभी भी आराजी खसरा नम्बर 1480 ग्राम रोधई का बेचान किसी भी व्यक्ति को नहीं किया गया है ना ही कब्जा दिया गया है और ना ही कोई लिखा पढी की है बल्कि वादी द्वारा बिना कारण उत्पन्न हुये अपील हाजा प्रस्तुत की गई है। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 14.09.2022 को पारित निर्णय में किसी भी प्रकार कोई त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।
8. हमारे द्वारा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। उभयपक्षकारान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

9. पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन से जाहिर आया कि विवादित आराजीयात जमाबंदी संवत् 2058 वाके ग्राम रोधई के खसरा नंबर 1480 परसादी पुत्र कुडेरी चमार सा. देह के नाम दर्ज रिकार्ड है। इसके नामान्तरण संख्या 1267 दिनांक 27.05.2000 मे लाल स्याही से अंकन है कि " परसादी फौत होने पर खाता काशीबाई बेवा गरीबा व रामप्रसाद,रिशीकेश, बन्टी पिसरान गरीबा 1/2 हल्के पुत्र सामलिया चमार 1/2 सा) देह0 के नाम स्वीकार हुआ है।"

मृतक परसादी के विरासत वारिसान रेस्पोजेन्ट/ प्रतिवादी सं० 03 के विशेष कथन के जिम्न नंबर 01 की ताईद विरासत नामान्तरण संख्या 1207 दिनांक 27.05.2001 य 03.03.2001 से होना प्रभावित है।

10. तहसीलदार के नामन्तरण संख्या 1207 दिनांक 03.03.2001 की अपील में अदालत मातहत द्वारा विवादित आराजीयात के खातेदारी अधिकार की घोषणा का वाद की घोषणा का वाद अदालत मातहत में 37/02 बउनवान हल्के बनाम विद्या देवी लम्बित रहते हुए नामान्तरण अपील को स्थगित करना चाहिए था ताकि मुकदमों की बहुलता न बढ़े। वैसे भी नामान्तरण कार्यवाही एक "फिस्कल प्रोसेडिंग" है न कि खातेदारी अधिकार निर्धारण की।

आदेश 07 नियम 11 जा० दी० के प्रावधान निम्नानुसार है-

(a) where it does not disclose a cause of action;

(b) where the relief claimed is undervalued, and the plaintiff, on being required by the Court to correct the valuation within a time to be fixed by the Court, fails to do so;

(c) where the relief claimed is properly valued, but the plaint is returned upon paper insufficiently stamped, and the plaintiff, on being required by the Court to supply the requisite stamp-paper within a time to be fixed by the Court, fails to do so;

(d) where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law:

अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 के दो प्रार्थना पत्र निर्णित हुए।

(1) दिनांक 16.03.2007 प्रार्थी हल्के (प्रतिवादी नंबर 03) द्वारा-

"मुख्य बिंदु:- वाद में मृतक परसादी के वारिसान को आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया गया"

(2) दिनांक 17.09.2022 प्रार्थिया विद्या देवी उर्फ लक्ष्मी देवी (रेस्पोजेन्ट सं० 02/1) द्वारा-

"मुख्य बिंदु:- तथाकथित विक्रय पर अनरजिस्टर्ड व अनस्टाम्पित से वाद कारण उत्पन्न नहीं"

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर



दोनों प्रार्थना पत्रों के अलग-अलग आधार हैं, व प्रार्थी भी अलग-अलग हैं। प्रार्थना पत्र आदेश 07-नियम-11 के दृष्टिगत वाद में वाद पत्र एवं जवाब दावा रैस्पों संख्या 01, 02, व 03 का शामिल मिसल है। प्रार्थना पत्र 07-नियम-11 के निर्धारण के लिए केवल वादपत्र में वर्णित तथ्यों को विचारण न्यायालय को देखना होता है। प्रार्थी प्रतिवादी को आदेश 07-नियम-11 के अन्तर्गत आवेदन पेश करने का अधिकार नहीं है। वाद में विधि व तथ्य का मिश्रित बिंदु अन्तर्निहित है। इस कारण प्रारम्भिक स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता है।

प्रश्नगत सम्पत्ति पर के संबंध में प्रश्न विवादास्पद है और साक्ष्य अभिलिखित के वाद निर्धारित किया जा सकता है। इस कारण यह नहीं कहा जा सकता है कि वाद पत्र कोई वाद प्रकट नहीं करता है। [2017 (3) डी.एच.जे. (राज) 1035]

11. उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांत आंशिक स्वीकार की जाकर अदालत मातहत के आदेश दिनांक 14.09.2022 बरनवान लैण्ड होल्डर बनाम जमना लाल वगैरह प्रार्थना पत्र 07-नियम-11 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली अदालत मातहत को इन निर्देशों के साथ पुनः प्रेषित की जाती है कि प्रकरण में निम्न तनर्कायात कायम करते हुए संबंधित पक्षकारान को विधिवत् सुनवाई का मौका देते हुए पुनः नए सिरे से निर्णय पारित करे-


(1) आया मृतक परसादी के वारिसान रैस्पोंडेन्ट संख्या 03 के जवाब दावा के विशेष कथन के जिम्मन नंबर 01 व पत्रावली में शामिल प्रदर्श-1 जमाबंदी संवत् 2058 वाके ग्राम रोधई भू अभिलेख क्षेत्र मण्डरायल मे अंकित लाल स्याही से अंकित टिप्पणी के अनुसार है ? [भार-प्रतिवादी सं० 03]

(2) आया मृतक परसादी द्वारा क्या रैस्पोंडेन्ट सं० 01 को विवादित आराजीयात का अवैध हस्तान्तरण विधि विरुद्ध किया गया है ? [भार-अपीलांत/वादी]

(3) आया रैस्पोंडेन्ट संख्या 01 बेदखली का दायी है ? [भार-अपीलांत/वादी]

उभयपक्षकारान को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 08.03.2023 को सुनवाई के लिए मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी मण्डरायल के समक्ष उपस्थित हों।

12. पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय सरेइजलास आज दिनांक 06.02.2023 को सुनाया गया।


(व्यक्तिगत रूप से)
राजस्व सचिव, माधोपुर,
सवाई माधोपुर